भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.457**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तंबाकू का अवैध बाजार

457. श्री मनीश तिवारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तंबाकू के अवैध बाजार में हो रही चिंताजनक वृद्धि की जानकारी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और 2015 से अवैध तंबाकू बाजार से वर्ष-वार अनुमानित राजस्व कितना है;

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान तंबाकू उत्पादों की तस्करी और अवैध व्यापार के कारण केंद्र सरकार को राज्यवार और वर्ष-वार अनुमानित राजस्व हानि कितनी है;

(ग) अवैध तंबाकू व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रवर्तन को मजबूत करने और कर चोरी रोकने के उपाय शामिल हैं:

(घ) क्या सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर उच्च कराधान के प्रभाव और अवैध व्यापार को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं, और

(च) क्या सरकार जन स्वास्थ्य उद्देश्यों को वैध तंबाकू किसानों और उद्योग के हितधारकों पर आर्थिक प्रभाव के साथ संतुलित करने के लिए किसी नीतिगत उपाय पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने चालू वित्त वर्ष में जून, 2025 तक लगभग 3.93 करोड़ सिगरेट जब्त की हैं। इसके अलावा,

सीजीएसटी जोन और डीजीजीआई ने चालू वित्त वर्ष में जून 2025 तक लगभग 104.38 करोड़ रुपये के कर के गुटका/चबाने वाली तंबाकू/सिगरेट/पान मसाला के 61 मामलों का पता लगाया है।

सरकार ने तम्बाकू उत्पादों और संबंधित उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए एक विशेष तंत्र शुरू किया है जिसमें पान मसाला, तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों (अविनिर्मित, हुक्का, चबाने वाली तंबाकू, नसफा, गुटखा) और तम्बाकू विनिमतियों सहित वस्तुओं की कुछ श्रेणियां कवर की गई है जिसमें विनिर्माताओं को विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विनिर्माण के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह प्रणाली प्रत्येक मशीन के लिए पंजीकरण, मासिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य करती है और इस हेतु मशीनों के लिए तकनीकी सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ-साथ तंबाकू और संबंधित उत्पादों के अवैध विनिर्माण और आपूर्ति को ट्रैक करने के लिए उत्पादन क्षमता और मशीन संचालन की रियल टाईम निगरानी आवश्यक है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम को वित्त अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित किया गया है, जो सरकार को विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए एक व्यापक ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र स्थापित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, ट्रैक एवं ट्रेस प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ट्रैक एवं ट्रेस तंत्र के उल्लंघनों के लिए विशेष रूप से दंड लगाने का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार एक विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) का पक्षकार है और इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन एफसीटीसी के (अनुच्छेद 15) के तहत अपनाए गए तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एफसीटीसी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 8 के अनुसार तंबाकू उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है।

******